

महाकाल श्रृंगार



ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का बुधवार को आकर्षक श्रृंगार किया गया।

खुसूर-फुसूर



संख्या देख यंत्रियों को डकार आई

मंदिर में हुए बड़े आयोजन के दौरान जमकर श्रद्धालु उमड़ें थे। संयोग अंतर्गत श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला पूरे 3 दिन निरंतर चलता रहा। लाखों की संख्या में भगवान के दर्शनों को श्रद्धालु आए और शहर में जमकर व्यवसाय चला। ई-रिक्शा वालों ने एक किलोमीटर के 300-500 रुपए तक कमाए हैं। सर्प पूजा वाले दिन तो जमकर कमाई का हाल रहा है। मंदिर में कमाई हुई तो बाहर वालों का कहना था हम भी कमाई करने आए हैं। इस सबसे परे 24 घंटों उपरांत दर्शनों की संख्या का आंकड़ा जो सामने आया है उसे लेकर पिछले दो दिनों से यंत्रियों को बार-बार डकार आ रही है। उन्हें उलटी करने का मन करने लगा है। ये एकाध नहीं कुछ ज्यादा जगह के यंत्री हैं। इनमें से एक जगह तो वो है जहां निर्माण की टेस्टिंग कर जांच रिपोर्ट दी जाती है। बात ही बात में वे 12 लाख का जिक्र करने से नहीं चुकते हैं और धीरे से इस पर बातों में सवाल उठाते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई का हिसाब बनाते हैं और फिर चौकाते हैं। ये कैसे संभव हुआ और किस तरह से हुआ। हर फार्मूला यहां आकर फेल हो रहा है। फिर 12 लाख की संख्या पर आते हैं और उन्हें डकार आने लगती है। वे सीधे बोलते हैं 24 घंटे में कुल 86400 सेकंड होते हैं। ब्रिज कुल 91 फीट लंबा और चौड़ाई: 10 फीट - 5 फीट आने, 5 फीट जाने की। इसकी क्षमता के अनुसार एक बार में 400 श्रद्धालु आ सकते हैं। पूल की मजबूती के लिए 5 स्तंभ का सहारा है। अब 12 लाख के लिए पूल की स्थिति को देखते हुए प्रति सेकंड 13 श्रद्धालुओं का दर्शन करना आवश्यक है। जब आने और जाने का रास्ता एक बार में 5-5 यानिकी कुल 10 का ही रास्ता है तो 13 के दर्शन कैसे हो गए। इस सवाल के उपजते ही यंत्रियों ने एक के बाद एक गणितज्ञों के फार्मूला खोले एवं पिछले तीन दिन से हिसाब लगा रहे हैं पर एक भी फार्मूला के तहत 24 घंटे यानिकी 86400 सेकंड में उक्त स्थान पर 12 लाख के दर्शनों का गणित उनके समक्ष में नहीं आ रहा है। खुसूर-फुसूर है कि बेवजह ही यंत्रियों ने अपना दिमाग खपाया और गणित लगाया। इसमें किसी भी प्रमेय और किसी बीज गणित, अंक गणित की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए दो और दो पांच करने वाला पहाड़ा आना चाहिए वो सिर्फ सत्यवादियों के यहां ही मिल सकता है। यही नहीं विकास के दौर में ही मिल सकता है। टेस्टिंग रिपोर्ट में ही एक समय में 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं को नहीं आने देने की स्थिति स्पष्ट थी तो फिर तो नया सवाल खड़ा हो गया है कि अधिक संख्या को ब्रिज पर लाकर श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ करने से भी जिम्मेदार नहीं चूके हैं।

- नैनो न्यूज

- मुस्लिम बहनों ने भी बांधी राखी, भाई-बहन के प्रेम का दिया संदेश
 - 26 अगस्त को निकलेगा मिलादुन्नी का जुलूस, 27 अगस्त को टंकी चौराहे पर होगा जलसा
 - माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे उज्जैन के छात्र
 - क्षीरसागर स्थित तिलक स्मृति मंदिर में संपन्न हुई वार्षिक साधारण सभा, आय-व्यय का लेखा-जोखा सर्वसम्मति से पारित
 - निर्मला कॉलेज के छात्र सैनिक आराध्य राष्ट्रीय साइबर डिफेंडर कैप के लिए चयनित
 - संस्कृति की जड़ों से जुड़कर ही संभव है समाज का लोकमंगल
 - तिरुपति बालाजी में होने वाले सावर्ध राष्ट्रीय अधिवेशन पर सरे समाज ने की चर्चा
 - स्वच्छता, संस्कृति का संदेश देकर चिंतामन जवासिथा से महाकाल तक निकली भव्य कलश यात्रा

ट्रेंडिंग



जबसे S.I.R. शुरू हुआ

बच्चे स्कूल में टीचर को दूंद रहे है

टीचर B.L.O बनकर बच्चों के माँ बाप को दूंद रहे है

माँ बाप 2002 की लिस्ट में अपने माँ बाप को दूंद रहे है







माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्णय से जिले के कई बच्चे होंगे लाभावित

माता-पिता नहीं हैं तो बोर्ड की नामांकन-परीक्षा फीस माफ

दैनिक अवन्तिका >> उज्जैन

माध्यमिक शिक्षा मंडल इस वर्ष की कक्षा 10वीं, 12वीं, द्वितीय बोर्ड परीक्षा, डीएलएड परीक्षा में माता-पिता को खो चुके विद्यार्थियों से न तो नामांकन की फीस लेगा और न ही परीक्षा का शुल्क ही लेगा। इसे लेकर बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं। जिले में ऐसे कई बच्चे इस निर्णय से लाभावित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी निकलवाई जा रही है। मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी एस के रेनीवाल के अनुसार आदेश के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के माध्यम से राहत मिलेगी।

जिन विद्यार्थियों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है उनसे माध्यमिक शिक्षा मंडल कोई शुल्क नहीं लेगा। माशिम ने इस संबंध

निर्णय से ऐसे विद्यार्थी न तो परीक्षा देने से वंचित रहेंगे न शिक्षा से



में एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि कई बार देखा गया है कि शुल्क के अभाव में ऐसे कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए बोर्ड ने तय किया है कि ऐसे बच्चों से नामांकन और परीक्षा दोनों तरह के

दस्तावेज के आधार पर पात्रता

शुल्क माफी का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को बोर्ड का नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरते समय माता और पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही जिस रिश्तेदार सरकारी अनाथालय या मान्यता प्राप्त संस्था में विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहा है, वहां से संबंधित प्रमाण-पत्र भी देना अनिवार्य होगा। तय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर विद्यार्थी शुल्क छूट का पात्र नहीं माना जाएगा।

शुल्क नहीं लिए जाएंगे। नए आदेश के मुताबिक जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है उन्हें सत्र 2026-27 से मंडल की परीक्षाओं और नामांकन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इसमें

ऐसे विद्यार्थी भी शामिल किए गए हैं जो माता-पिता की मृत्यु के बाद किसी रिश्तेदार के आश्रय में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अथवा शासन द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त अनाथालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें

नामांकन एवं फीस में शुल्क वृद्धि

माशिम ने इस बार 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा का शुल्क 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया है। वहीं नामांकन शुल्क भी 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। वहीं डीएलएड परीक्षा शुल्क 7000, डीएलएड परीक्षा द्वितीय अवसर के दो विषय के लिए 3000 रुपए, चार विषय के लिए 5000 रुपए और चार से अधिक विषय के लिए 7000 रुपए शुल्क लगेगा। ऐसे में अनाथ विद्यार्थियों को इन शुल्कों से पूरी तरह छूट मिलने से उनके परिवार या आश्रयदाताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।

उद्देश्य पढ़ाई प्रभावित न हो

क्षेत्रीय अधिकारी रेनीवाल के अनुसार माशिम के इस फैसले का उद्देश्य माता-पिता को खो चुके विद्यार्थियों की शिक्षा को आर्थिक कारणों से प्रभावित होने से रोकना है। परीक्षा और नामांकन शुल्क माफ होने से ऐसे बच्चों पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम होगा। उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।

शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। यह सुविधा माशिम की ओर से आयोजित 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, द्वितीय बोर्ड परीक्षा, डीएलएड जैसी परीक्षाओं और नामांकन पर लागू होगी।

सीएम यादव ने किया 945 करोड़

के एलिवेटेड ब्रिज का भूमिपूजन



दैनिक अवन्तिका >> उज्जैन

बुधवार शाम उज्जैन गृह नगर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन को एलिवेटेड ब्रिज की सांगत दी है। उन्होंने उज्जैन शहर में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर (इंदिनगर चौराहा से नीलगंगा चौराहा तक एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक) - कुल लंबाई 5.30 कि.मी. का भूमिपूजन किया। ब्रिज की लागत 945.20 करोड़ है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत होमगार्ड द्वारा कालिदास एकेडमी में प्रदर्शित किए गए आपदा प्रबंधन उपकरणों एवं बचाव कार्य में उपयोग होने वाले आधुनिक संसाधनों का अवलोकन किया। इस दौरान होमगार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विभिन्न आपदा प्रबंधन यंत्रों की कार्यप्रणाली एवं उनके उपयोग की जानकारी दी। इन

उपकरणों का उपयोग बाढ़, आगजनी, भवन दुर्घटना, सड़क हादसे तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य के दौरान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों एवं जवानों के प्रयासों की सराहना की। इससे पूर्व पुलिस लाइन स्थित हैलीपैड पर राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ, विधायक अनिल जैन कालूहैड़ा, अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण रावि सोलंकी, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, अध्यक्ष महापौर मुकेश टटवाल, संभागायुक्त अशोक सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी ने उपस्थित होकर उनका स्वागत किया।

28 अगस्त को मनेगा रक्षाबंधन

सुबह 9.48 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण भी रहेगा

दैनिक अवन्तिका >> उज्जैन

भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि दो दिन रहने के कारण 27 और 28 अगस्त को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उदयतिथि के आधार पर 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया शुभ माना जा रहा है।

27 अगस्त को शुरू होगी पूर्णिमा- पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9.08 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह 9.48 बजे तक रहेगी। चूंकि 28 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा विद्यमान रहेगी, इसलिए इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा।

सुबह 5.57 से 9.48 बजे तक राखी बांधना शुभ- इस वर्ष राखी बांधने के लिए सुबह का समय विशेष शुभ बताया गया है। 28 अगस्त को सुबह 5.57 बजे से 9.48 बजे तक राखी बांधी जा सकेगी। इस अवधि में भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। चौघड़िया के अनुसार



भद्रा को लेकर नहीं रहेगा संशय

रक्षाबंधन पर भद्रा में राखी बांधना परंपरागत रूप से वर्जित माना जाता है। इस बार उपलब्ध पंचांग गणनाओं के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, इसलिए 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के लिए भद्रा बाधा नहीं बनेगी।

इस बार सुबह ही राखी बांधने पर जोर

रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भले ही 27 और 28 अगस्त के बीच भ्रम रहा हो, लेकिन अधिकांश पंचांग गणनाएं 28 अगस्त को पर्व मनाने पर सहमत हैं। खास बात यह है कि इस बार सुबह ही राखी बांधने का अच्छा अवसर उपलब्ध है। इसलिए परिवारों के लिए बेहतर रहेगा कि वे 28 अगस्त की सुबह 9.48 बजे से पहले राखी बांधने की तैयारी पूरी कर लें।

सुबह के समय भी अलग-अलग शुभ अवधि बताई गई है। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार सुबह 5.57 से 7.33 बजे तक चर-सामान्य, 7.33 से 9.10 बजे तक लाभ-उन्नति और 9.10 से 10.46 बजे तक अमृत-सर्वोत्तम समय बताया गया है। हालांकि पूर्णिमा तिथि 9.48 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए रक्षाबंधन संस्कार के लिए 9.48 बजे तक का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

खुले में कचरा फेंकने पर होटल संचालक पर लगाया जुर्माना

दैनिक अवन्तिका >> उज्जैन

शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने चालानी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को वार्ड क्र. 33 में बड़ा गणेश मंदिर के समीप स्थित गली में खुले में कचरा फेंकने पर होटल कर्मा पैलेस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को उक्त क्षेत्र में खुले में कचरा फेंके जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान होटल संचालक द्वारा खुले में कचरा फेंका जाना पाए जाने पर निगम ने नियमानुसार चालानी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी कालूराम सोलंकी और स्वच्छता निरीक्षक मनीष पांडे द्वारा की



गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित को समझाईश देते हुए भाविष्य में सार्वजनिक स्थान पर कचरा नहीं फेंकने और कचरे का उचित तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम द्वारा शहरवासियों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लगातार अपील की जा रही है कि कचरा खुले में न फेंके और निर्धारित स्थान पर ही कचरा डालें। निगम का कहना है कि उज्जैन धार्मिक और पर्यटन नगरी है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

प्रतिबंध के बावजूद भीड़भाड़ में दौड़ रहीं यात्री व स्कूल बसें

शहर में किसी रोज हो सकता है हादसा, ट्रैफिक पुलिस को मिले ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई के अधिकार

दैनिक अवन्तिका >> उज्जैन

शहर में तेज रफ्तार और अनियंत्रित गति से दौड़ रही यात्री एवं स्कूल बसें कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती हैं। उज्जैन-इंदौर की कई यात्री बसें प्रतिबंध के बावजूद नानाखेड़ा से आकर तीन बत्ती चौराहे से होकर भीड़भाड़ वाले मार्ग से देवास गेट तक पहुंच रही हैं।

प्रहंगंज से चामुंडा माता मार्ग पर घंटाघर से ही यातायात का दबाव बढ़ जाता है। ई-रिक्शा, ऑटो,



बाइक और कारों की भीड़ के बीच यात्री एवं स्कूल बसें निकलती हैं। कई बस चालक तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न बजाते हुए भीड़भाड़ में वाहन दौड़ाते हैं, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा बना रहता है।

अतिरिक्त पुलिस बल को दिया जाए विशेष प्रशिक्षण

यातायात नियंत्रित करने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। सुझाव है कि इन पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर भीड़भाड़ वाले मार्गों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाए। साथ ही उन्हें नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई करने के पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। यात्री और स्कूल बसों की तेज गति, प्रतिबंधित मार्ग पर संचालन और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था हो। पुलिसकर्मियों को आवश्यक अधिकार मिलने से नियम तोड़ने वालों पर मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी और भाविष्य में किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सकेगा।

महाकाल लोक के फुड जोन में नेमा कुल्फी सेंटर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

गंदगी और चूहे मिलने पर लाइसेंस निलंबित

फालूदा-कुल्फी के नमूने जांच के लिए भेजे

दैनिक अवन्तिका >> उज्जैन

श्रावण मास में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। इसी बीच खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर उज्जैन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजार में बिक रहे दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत 19 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच और नमूना कार्रवाई की। महाकाल लोक



स्थित नेमा कुल्फी फालूदा, शॉप नंबर-2, मिडवे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर विभाग ने प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करते हुए खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मौके पर खाद्य व्यवसाय भी बंद करवाया गया।

स्टोरेज एरिया में गंदगी, चूहों की मौजूदगी मिली- निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के स्टोरेज एरिया में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। विभागीय टीम को वहां गंदगी के साथ चूहों की मौजूदगी भी मिली। खाद्य सामग्री के भंडारण वाले स्थान पर इस प्रकार की स्थिति सामने आने से खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका को लेकर विभाग ने गंभीरता दिखाई और कार्रवाई की।

फालूदा और केसर-पिस्ता कुल्फी के नमूने लिए

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नेमा कुल्फी फालूदा से फालूदा सेवइया और केसर-पिस्ता कुल्फी के नमूने लिए। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीन प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने अन्य प्रतिष्ठानों से भी खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। महादेव बाटी भंडार, देवास गेट बस स्टैंड से तुअर वाल और बाटी के नमूने लिए गए। वहीं सपना स्वीट्स, रेलवे स्टेशन उज्जैन से मलाई बर्फी और काजू कतली के नमूने लिए गए।



॥ उस भी महकाल ॥

96692 77337
88398 20109

शोभाश्री
ऑटोमोबाइल

इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा व अन्य ई-वाहन एवं पार्ट्स के होलसेल व रिटेल विक्रेता





इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा व अन्य ई-वाहन एवं पार्ट्स के होलसेल व रिटेल विक्रेता

नक्षत्र होटल चौराहा, मक्सी बायपास मेन रोड, उज्जैन

दैनिक अवन्तिका

सब पे नज़र, सबकी ख़बर

इंदौर | उज्जैन | शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 | www.awantika.com 03

न्यूज़ ब्रीफ

इंदौर जिले में जन-विश्वास शिविर आज शुक्रवार को

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत 20 अगस्त को विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लसुडिया परमार के पंचायत भवन में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। जन-विश्वास शिविर में इंदौर से अधिकारियों का दल सुबह साढ़े आठ बजे सांवेर के लिए रवाना होगा। शिविर में बुढ़ी बरलाई, पीरकराड़िया, पुवांड्राहपा, पुवाडांदाई, बरलाई जागीर, मकोडिया, मांगलिया सड़क, सुल्लाखेड़ी, रामपिरल्या, ढाबली, डकाया, पलासिया, माण्डलावदा, लसुडिया परमार के नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। शिविर के दौरान जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की शासकीय संस्थाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का मैकनी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की स्थिति देखी जाएगी। अभियान के अंतर्गत जनसंबाद के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी।

क्षेत्र और आसपास के सैकड़ों युवाओं को मिला रोजगार

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विकास और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। वर्ष 2014 के पहले के भारत और उसके बाद के भारत में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। आज भारत का नवीन स्वरूप पूरी दुनिया के सामने उभरकर आया है। मध्यप्रदेश भी इसी विकास यात्रा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज पीएमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित 2 आधुनिक औद्योगिक इकाइयों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज से प्रारंभ हुई नई औद्योगिक इकाइयां विकास और समृद्धि की नई धारा को आगे बढ़ाएंगी।

प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर

इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और अवसर प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसिलिंग चरण की अतिथि 21 से 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस चरण में विद्यार्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों पर रहस्यले आओ, पहले पाओरे के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त सीटों पर निर्धारित अतिथि में प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि पात्र विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण कराते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराए।

एकलव्य विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए



इंदौर। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव रंजना चोपड़ा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान एवं धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संभागप्राप्त कार्यालय इंदौर में सम्पन्न हुई। बैठक में दोनों अभियानों के अंतर्गत संभाग के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज की बड़ी आबादी निवास करती है। इसलिए जनजातीय वर्ग के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रेमिया एवं केंद्रीय विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हिस्साधियों के आयुभारमां निधिशरित समय-सीमा में बनाए जाएं तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

नैनो न्यूज

- देवास – तिरंगा यात्रा में मधुमक्खियों का हमला:** देवास के ग्राम राला मंडल क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे कई लोग प्रभावित हुए।
- रतलाम – मंडी में प्याज की बंपर आवक:** रतलाम मंडी में प्याज की बंपर आवक से महु-नीमच रोड पर यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बनी।
- मंदसौर – मुपत् किताबों पर छात्रों का प्रदर्शन:** मंदसौर में त्रैमासिक परीक्षा नजदीक आने के बावजूद मुपत् किताबें नहीं मिलने पर प्दीवीपी और छात्रों ने प्रदर्शन किया।
- नीमच – अस्पताल व्यवस्था फिर सवालें में:** नीमच की ताजा खबरों में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को अस्पताल से बाहर निकालने के बाद सड़क पर प्रसव होने का मामला सामने आया।
- शाजापुर – बारिश से मौसम सक्रिय:** शाजापुर समेत पश्चिमी मध्यप्रदेश में मानसून सक्रिय है। जिले में आगामी दिनों में तेजे बारिश की संभावना के चलते प्रशासन को सतर्कता की जरूरत है।
- आगर-मालवा – बारिश का असर जारी:** आगर-मालवा में भी मानसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने से सरकार में था स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व, अब मुख्यमंत्री के पास कई महत्वपूर्ण विभाग

शिवराज सरकार में बंटा था काम, मुख्यमंत्री के पास कई महत्वपूर्ण विभाग

दैनिक अवन्तिका ►► इंदौर

मध्यप्रदेश की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी होने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बहस तेज हो गई है। सवाल यह है कि जब भाजपा में अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी टीम मौजूद है, तो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का अधिक विकेंद्रीकरण क्यों नहीं किया जा रहा।

मोहन यादव सरकार के शुरूआती विभागीय बंटवारे में मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन और प्रवासी भारतीय विभाग सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपने पास रखी थीं। साथ ही जो विभाग किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं थे, वे भी मुख्यमंत्री के पास थे।

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

उज्जैन में एच1 एन1 से पीड़ित महिला की मौत

31 जुलाई को एच1 एन1 पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट, इंदौर में उपचार के दौरान 60 वर्षीय सरोज नागर ने तोड़ा

दैनिक अवन्तिका ►► उज्जैन

शहर में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। ऋषि नगर एक्सटेंशन निवासी 60 वर्षीय सरोज नागर की इंदौर के कोकिलाबेन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला को ल्हा1 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई दिनों तक उपचार चला, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सका। इस घटना को मध्यप्रदेश में इस सीजन में एच1एन1 से हुई पहली मौत बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार सरोज नागर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उज्जैन के अर्बती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान उनके सैपल में

इन्फ्लुएंजा-ए तथा 2009 एच1एन1 वायरस की पुष्टि हुई। इसके बाद हालत

गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां कोकिलाबेन अस्पताल में उनका उपचार जारी रहा। करीब दो से तीन सप्ताह के उपचार के बाद बुधवार को उनकी मौत हो गई।

महिला में एच1एन1 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने वार्ड क्रमांक 49 में उनके घर के आसपास सर्वे कराया था। विभाग के अनुसार आसपास के करीब 28 घरों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई और किसी अन्य व्यक्ति में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण नहीं पाए गए। हालांकि, अब महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर

इंदौर में हुए 100 करोड़ के घोटाले में 32 आरोपी बनाए

इ्रेनेज घोटाले में ईडी ने किया चालान पेश

दैनिक अवन्तिका ►► इंदौर

इंदौर के चर्चित 100 करोड़ रुपये के इ्रेनेज लाइन घोटाले में ईडी ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। इस घोटाले में ईडी ने 32 आरोपियों को बनाया है, जिमेंमें इंजीनियर, लेखा विभाग के कर्मचारी और टेक्रेदार शामिल हैं। उधर, जेल में बंद दो आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पेश किए गए चालान में चीफ इंजीनियर अभय राठौर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बौर काम किए फाइल मंजूर करने और लेखा विभाग के कर्मचारियों की मदद से बिल मंजूर कराने के खेल में अभय माहिर था।

चार साल में 100 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की फर्जी फाइल तैयार कर लेखा विभाग में बिल भुगतान के लिए भेजे गए थे। जब इसकी शिकायत बड़े अफसरों के कानों तक पहुंची तो जांच शुरू हुई।

यह है फर्जी बिल घोटाला

आरोपितों ने नगर निगम में फर्जी टेंडर तैयार किए। कागज पर फर्जी काम बताया गया। जाली वर्क आर्डर और फर्जी बिल भी बनाए। झूठे कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए और निगम से 103 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान प्राप्त कर लिया। जांच में यह बात सामने आई थी कि कई काम कभी किए ही नहीं गए। कुछ काम पहले ही पूरे हो चुके थे। इसके बावजूद उन्हीं कामों के नाम पर भुगतान हुआ।

इस बीच घोटाले की फाइलें नगर निगम के एक अधिकारी की कार से गायब हो गईं। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर घोटाले की परतें खुलती चली गईं। बाद में इस केस में ईडी की एंट्री हुई और उसने आरोपियों की संपत्तियां अटैच करना शुरू कीं। ईडी ने जो चालान कोर्ट में पेश किया है, वह 20 हजार पेज से ज्यादा का है और 32 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

ईडी ने पिछले साल अगस्त में आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारकर 200 करोड़ रुपये की संपत्ति, खाते और

पत्रकार संगठनों की बढ़ती परेशानी से उठे सवाल

जनसंपर्क विभाग को पूर्णकालिक मंत्री की दरकार, मुख्यमंत्री पर कई विभागों का बोझ

भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं मिलने से उठने लगे सवाल

दैनिक अवन्तिका ►► भोपाल

मध्यप्रदेश में जनसंपर्क विभाग को पूर्णकालिक राजनीतिक नेतृत्व दिए जाने की मांग अब केवल पत्रकारों तक सीमित नहीं रह गई है। विभिन्न पत्रकार संगठन भी अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संगठनों का कहना है कि उनकी बात सुनने और सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए जिम्मेदार राजनीतिक स्तर पर स्थायी व्यवस्था।

होना जरूरी है।

वर्तमान व्यवस्था में मुख्यमंत्री के पास पहले से कई महत्वपूर्ण विभागों और जिम्मेदारियों का दायित्व है। ऐसे में उनसे जब अपेक्षा करना कि वे पत्रकारों, संपादकों और मीडिया संगठनों की प्रत्येक समस्या के लिए नियमित रूप से समय निकाल सकें, व्यावहारिक नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ पब्लिशिंग अधिकारियों के पास भी अनेक महत्वपूर्ण दायित्व हैं। ऐसे में पत्रकारों के बीच यह सवाल उठ रहा

भाजपा में अनुभवी

नेताओं की कमी नहीं

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि भाजपा के पास प्रदेश में कई वरिष्ठ, अनुभवी और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता मौजूद हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में जनसंपर्क जैसे संवेदनशील विभाग का राजनीतिक नेतृत्व लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पास रहने को लेकर पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा के अंदर यह भावना भी बताई जा रही है कि वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां देकर उनका अनुभव सरकार के कामकाज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लगातार बढ़ती प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त विभाग रहने से कार्यकताओं और नेताओं के बीच भी असंतोष की स्थिति बनने की चर्चाएं हैं।

है कि जब कोई गंभीर समस्या सामने आए तो अपनी बात आखिर किसके समक्ष रखी जाए।

प्रदेश के पत्रकार संगठन समझा सकते हैं कि अधिमान्यता, विज्ञापन नीति, पत्रकार सुरक्षा, छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की समस्याओं, आर्थिक

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को और जिम्मेदारी देने की मांग

राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि भाजपा के पास ऐसे कई नेता हैं, जिन्हें प्रशासन और संगठन का लंबा अनुभव है। यदि उन्हें अतिरिक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है तो मुख्यमंत्री का बोझ कम हो सकता है और विभागीय निर्णय प्रक्रिया को भी गति मिल सकती है। यह मुद्दा केवल जनसंपर्क विभाग तक सीमित नहीं है। गृह, प्रशासन, निवेश, खनिज, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, पशुपालन सहित मुख्यमंत्री के पास मौजूद तमाम विभागों को लेकर यह बहस है कि क्या जिम्मेदारियों का और बेहतर बंटवारा किया जाना चाहिए।

पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर सरकार के कामकाज को व्यापक राजनीतिक नेतृत्व मिला था। मुख्यमंत्री पद को लेकर समय-समय पर सामने आने वाली चर्चाओं को

भी इसी राजनीतिक वातावरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाओं का बार-बार सामने आना यह संकेत जरूर देता है कि सरकार के भीतर जिम्मेदारियों के बंटवारे और नेतृत्व

विभागों के बंटवारे

से राजनीतिक संदेश भी

सरकार में विभागों का वितरण केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी होता है। वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपने से पार्टी के भीतर उनकी भूमिका स्पष्ट होती है और संगठन के अनुभवी चेहरों का सरकार में उपयोग भी बढ़ता है। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि यदि मुख्यमंत्री के पास विभागों का बोझ कम किया जाता है और वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो इससे सरकार की कार्यक्षमता के साथ-साथ भाजपा के अंदर का संतुलन भी बेहतर हो सकता है।

शैली को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। अब सवाल यह है कि क्या मोहन सरकार मुख्यमंत्री के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण विभाग वरिष्ठ और अनुभवी भाजपा नेताओं को सौंपकर सरकार के कामकाज को और अधिक विकेंद्रीकृत करेगी?

मुस्लिम समुदाय ने सौंपे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

यूसीसी के खिलाफ मध्यप्रदेश में शक्ति प्रदर्शन

दैनिक अवन्तिका ►► भोपाल

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में मध्यप्रदेश में मुस्लिम समुदाय ने एक साथ आवाज बुलंद की। विधायक आरिफ मसूद के आह्वान पर प्रदेश के करीब 50 जिला मुख्यालयों पर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यूसीसी को वापस लेने की मांग की। कई जगह महिलाओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। राजधानी भोपाल में 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर समान नागरिक संहिता का विरोध दर्ज कराया। आरिफ मसूद ने कहा कि यूसीसी के खिलाफ विरोध केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा। आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार से यूसीसी को वापस लेने की मांग जारी रहेगी। विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि यूसीसी के खिलाफ आंदोलन का यह पहला चरण है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में मध्यप्रदेश में मुस्लिम समुदाय ने एक साथ आवाज बुलंद की। विधायक आरिफ मसूद के आह्वान पर प्रदेश के करीब 50 जिला मुख्यालयों पर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यूसीसी को वापस लेने की मांग की। कई जगह महिलाओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। राजधानी भोपाल में 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर समान नागरिक संहिता का विरोध दर्ज कराया। आरिफ मसूद ने कहा कि यूसीसी के खिलाफ विरोध केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा। आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार से यूसीसी को वापस लेने की मांग जारी रहेगी। विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि यूसीसी के खिलाफ आंदोलन का यह पहला चरण है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

वार्ड 6 में 40 लाख की लागत से पुलिया निर्माण का भूमिपूजन

दैनिक अवन्तिका ►► इंदौर

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

इंदौर जिले में पीओपी एवं रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध

आशा मनोज गायरी जी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद के सभी पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं वार्ड सहित नगर नलखेड़ा के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पुलिया निर्माण से वार्ड क्रमांक 06 के नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर नगर

नलखेड़ा एवं वार्ड क्रमांक 06 की जनता ने पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत कराने एवं विकास कार्य की सौगात देने के लिए नगर परिषद नलखेड़ा तथा वार्ड क्रमांक 06 की पार्षद श्रीमती आशा मनोज गायरी का आभार व्यक्त किया

जनसंपर्क विभाग केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तक सीमित विभाग नहीं है। यह सरकार और पत्रकारिता जगत के बीच संवाद का महत्वपूर्ण सेतु भी है। इसलिए विभाग के पास पूर्णकालिक राजनीतिक नेतृत्व होना आवश्यक है।

कठिनाइयों तथा अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर नियमित संवाद का अभाव होने से कई

मांगों के समाधान में अपेक्षित गति नहीं आ पाती। मीडिया जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि

जनसंपर्क विभाग केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तक सीमित विभाग नहीं है। यह सरकार और पत्रकारिता जगत के बीच संवाद का

महत्वपूर्ण सेतु भी है। इसलिए विभाग के पास पूर्णकालिक राजनीतिक नेतृत्व होना आवश्यक है।

